सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य

सीएम ने नए वर्ष की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को लेकर पहली बार अफसरों के साथ बैठक की

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. प्रदेश में कोविड काल से ही सरकारी कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाद में सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया था.

लेकिन दूसरे कार्यालय तो छोड़ दें, मंत्रालय में ही अधिकारी-कर्मचारी तय समय पर नहीं पहुंचते. लिहाजा अब आने वाले दिनों में इस मामले में सख्ती हो सकती है और सरकारी कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेस को अनिवार्य किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इस संबंध में संकेत दिये हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बड़ी बैठक की. बैठक में वर्ष 2026 के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्माण परियोजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया, बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के

साथ ही सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित पुलिस तथा भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस दौरान बैठक में सीएम ने कहा कि कोविड काल से प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है. इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कार्यालयीन समय को बढ़ाना और सभी के द्वारा उसका अनुसरण आवश्यक है. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में प्रात: 10 बजे से कार्य आरंभ हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सहित अन्य तकनीकी प्रणालियों का सहारा लिया जाए. इससे अनुशासन के साथ कार्य निष्पादन में भी सुधार होगा.

मिशन मोड पर काम करना होगा

बैठक में सीएम ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और उन्नति को अधिक गति देने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा. प्रदेश में विकास गतिविधियों का तेजी से क्रियान्वयन हो और जनकल्याणकारी योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को सुगमता से लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही तय करने की व्यवस्था को सशक्त करना होगा . वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. हमारा लक्ष्य समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 12 जनवरी से 31 मार्च संकल्प से समाधान अभियान-वन आरंभ किया जा रहा है. यह अभियान 106 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं पर केंद्रित होगा. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि शिविरों में प्राप्त समस्त आवेदनों का अंतिम निराकरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से हो.

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कमाण्ड क्षेत्र विकास का आधुनिकीकरण एमसीएडी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट एसपीएमयू का गठन किया है.

समिति में आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास जल संसाधन, प्रमुख अभियंता जल संसाधन, सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, योजना से संबंधित मुख्य अभियंता जल संसाधन/एनवीडीए, संचालक कृषि एवं किसान कल्याण, संचालक उद्यानिकी, संचालक हाइड्रोलॉजी बोधी, जल संसाधन, संचालक सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, जल संसाधन, योजना से संबंधित अधीक्षण यंत्री जल संसाधन/ एन.वी.डी.ए, योजना से संबंधित कार्यपालन यंत्री जल संसाधन/ एनवीडीए सदस्य होंगे. मुख्य अभियंता बोधी जल संसाधन को सदस्य सचिव नामित किया गया है.

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के दायित्व अनुसार मॉडल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करने के लिए जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से रूप रेखा तैयार करवाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन को लागू किया जाएगा.

इंदौर-उज्जैन मेट्रो रेल की डीपीआर प्रस्तुत

48 किमी की इंदौर उज्जैन मेट्रो

05 साल में पूरी होगी योजना

वीरेंद्र वर्मा

इंदौर. इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो रेल चलाने के लिए डीपीआर तैयार हो गई है और एमपी मेट्रो को प्रस्तुत कर दी गई . डीपीआर में उक्त योजना पर करीब 12 हजार करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है। योजना का कार्य 5 साल में पूरा होगा। उक्त योजना में उज्जैन शहर में 5 किलोमीटर अंडर ग्राउंड लाइन डाली जाएगी। साथ ही इंदौर से उज्जैन के बीच 11 स्टेशन प्रस्तावित है।

इंदौर उज्जैन के बीच प्रस्तावित

मेट्रो रेल की दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मध्यप्रदेश मेट्रो को प्रस्तुत कर दी है। उक्त डीपीआर में इंदौर से उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर लाइन डाली जाएगी, जिसमें 5 किलोमीटर उज्जैन शहर में अंडर ग्राउंड लाइन होगी। उक्त 48 किलोमीटर लंबी लाइन में 11 स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत डीपीआर में 12 हजार करोड़ रुपए लागत आएगी। पहले उक्त योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था।

उज्जैन शहर में 5 किलोमीटर अंडर ग्राउंड लाइन के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त योजना को बजट के पहले मंजूरी देने की चर्चा है, क्योंकि देश के आम बजट में उक्त योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जा सके। इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रस्तावित योजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की मंशा मेट्रो को सिंहस्थ के पहले पूरी करने की है। उक्त योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही प्रदेश सरकार टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देगी।

एक नजर में

प्रस्तावित लागत : 12 हजार करोड़ रुपए
कुल लंबाई : 48 किलोमीटर
उज्जैन में अंडर ग्राउंड लाइन: 5 किलोमीटर
स्टेशन संख्या : 11
कार्य पूरा करने का लक्ष्य : 5 साल

प्रदेश में अब तक 43 लाख 17 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी

भोपाल. प्रदेश में अभी तक 6 लाख 56 हजार 875 किसानों से 43 लाख 17 हजार 504 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रूपये प्रति क्विंटल है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि धान विक्रय के लिए किसान 13 जनवरी तक स्लॉट बुक करा सकते हैं. उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि निर्धारित समय पर स्लॉट बुक जरूर करा लें. धान की खरीदी 20 जनवरी तक की जायेगी. किसानों को 6791 करोड़ रूपये से अधिक राशि का भुगतान भी किया जा चुका है.

पानी में हैजा बैक्टीरिया मिलने का दावा

20 की मौत, 1 हजार से अधिक बीमार

विशेष संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. इंदौर में कथित रूप से दूषित पेयजल के सेवन से 20 लोगों की मौत और 1,000 से अधिक नागरिकों के गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में कांग्रेस ने भाजपा-नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश सरकार पर बोला हमला .

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इस घटना को 'बेहद चौंकाने वाली' बताया और सरकार पर असंवेदनशीलता तथा जवाबदेही तय करने में पूरी तरह

विफल रहने का सरकार पर आरोप लगाया. डॉ. नायक ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाल ही में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, जहां पीड़ितों ने सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद अब तक केवल चार परिवारों को ही दो लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इंदौर के प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. पार्टी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कथित रूप से पत्रकारों के साथ अभद्रता की भी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताया. और आगे चिंता जताते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि पानी में हैजा बैक्टीरिया पाया गया है और सवाल उठाया कि क्या इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई. पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में राज्य स्तरीय 'न्याय यात्रा' निकालने की घोषणा की है.

पेज एक का शेष

24 नए मरीज सामने आए...

इस दौरान 189 मरीजों का फॉलोअप लिया. साथ ही क्षेत्र में ओआरएस बनाने की विधि, हाथ धोने के सही तरीके और उल्टी दस्त से बचाव व उपचार से संबंधित जागरूकता सामग्री का वितरण किया. विभाग ने 686 ओआरएस और जिंक किट भी बांटीं. इधर, नर्मदा जल की पाइप लाइनों की सफाई का कार्य जारी है. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि पाइप लाइन शुद्धिकरण पूरा होने तक भागीरथपुरा क्षेत्र के निवासी नर्मदा जल का उपयोग न करें. इसके लिए 6 जनवरी की शाम और 7 जनवरी की सुबह मेगा माइकिंग कर पूरे प्रभावित इलाके में सतर्कता संदेश प्रसारित किया. जिलाधीश के निर्देश पर क्षेत्र में मरीजों के परिवहन के लिए दो एम्बुलेंस तैनात की गई हैं. इसके साथ ही 24 घंटे चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है. गंभीर मरीजों को एमवाय अस्पताल और अरविंदो अस्पताल में, जबकि बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल रेफर किया जा रहा है. जो मरीज निजी अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं, वहां भी निःशुल्क इलाज, जांच और दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं. वहीं जिन मरीजों की मौत हुई है, उनमें बुजुर्गों और पहले से कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों की संख्या अधिक है. इलाज के दौरान कुछ मरीजों की हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन बाद में अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। विभाग अब मौतों के हर मामले का अलग अलग मेडिकल ऑडिट कराने की तैयारी कर रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संक्रमण की गंभीरता किस स्तर तक पहुंच गई थी.

पूर्ण दक्षता से सुरक्षा जिम्मा संभालेगी 'कोर'

- महाकाल मंदिर प्रशासक जल्द सौंपेंगे कंपनी को वर्क आर्डर
- नई सुरक्षा कंपनी के गार्डों को दी जा रही ट्रेनिंग
- फिलहाल मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रही क्रिस्टल

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, महाकाल मंदिर और अन्य देवालय शिवालय के विषय में पुख्ता जानकारी के साथ ही आगमन, निर्गम और मंदिर की गतिविधियों की समस्त कार्य प्रणाली सुरक्षा कंपनी के गार्डस को पता होना चाहिए, ऐसे में पूर्ण दक्ष होने के मद्देनजर मंदिर की नई सुरक्षा कंपनी 'कोर' को ट्रेनिंग दी जा रही है.

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालु-अनुकूल बनाने की दिशा में मंदिर समिति ने तय प्रक्रिया के तहत नया टेंडर आमंत्रित किया था. इस टेंडर में दिल्ली की कौर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अंतिम मुहर लगी है. मंदिर समिति द्वारा कंपनी को सुरक्षा व्यवस्था के बदले प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि का अनुबंध दिया गया है.

अभी क्रिस्टल के पास जिम्मा-फिलहाल महाकाल मंदिर की सुरक्षा महाराष्ट्र स्थित क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसका टेंडर समाप्त हो चुका है. क्रिस्टल कंपनी का टर्नओवर लगभग 475 करोड़ रुपये रहा है और यह देश के कई प्रतिष्ठित स्थानों पर सुरक्षा सेवाएं दे चुकी है. मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान के निवास 'मन्नत', एचडीएफसी, मुंबई नगर निगम, फिनिक्स मॉल और एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा का दायित्व भी इसी कंपनी के पास रहा है. ऐसे में मंदिर समिति ने नई कंपनी कौर सर्विसेज को कार्यभार सौंपने से पहले उसे आवश्यक अनुभव दिलाने का निर्णय लिया है.

जय श्री महाकाल के उद्घोष से संबोधन

इसी क्रम में कौर सर्विसेज के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं भी प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा नए सुरक्षा गार्डों की भर्ती कर उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. यह प्रशिक्षण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महाकाल मंदिर की आध्यात्मिक परंपरा, धार्मिक मर्यादा और अतिथि-सत्कार की संस्कृति पर भी केंद्रित है. सुरक्षा कर्मियों को यह सिखाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं, साधु-संतों और अतिथियों से किस प्रकार विनम्र व्यवहार करना है, प्रवेश करते ही 'जय श्री महाकाल' के उद्घोष के साथ उनका स्वागत कैसे करना है तथा उन्हें मंदिर में आने-जाने के मार्गों की सही जानकारी कैसे देनी है.

हथियारबंद गार्ड के साथ 1000 की संख्या

नई व्यवस्था के अंतर्गत महाकाल मंदिर परिसर में कुल लगभग एक हजार सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे. इनमें कुछ प्रशिक्षित हथियारबंद गार्ड शामिल रहेंगे, जबकि शेष सुरक्षाकर्मी मेटल डिटेक्टर, हैंड मेटल डिटेक्टर, वॉकी-टॉकी जैसे आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होंगे. कंपनी को शीघ्र ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा, जिसके बाद वह औपचारिक रूप से मंदिर की संपूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारी संभालेगी.

पेज एक का शेष

विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं करता...

मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन की थी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीबी जी-राम-जी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी. यह गरीबों, खेतीहर मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है. इस योजना से गांवों के विकास को भी मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे प्रदेश के विकास के लिये सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं, जिससे कि सभी के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिले, विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीबी जी-राम-जी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है. इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है, बीज बुवाई एवं फसल कटाई की व्यस्ततम समयावधि को भी रोजगार उपलब्ध कराने की अवधि में शामिल किया जा सकेगा. प्रावधान के अनुसार इस अवधि में अधिनियम के तहत शामिल अन्य कार्य नहीं किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में पहले 6 प्रतिशत प्रशासनिक अमला तैनात किया गया था. विकसित भारत जी-राम-जी योजना में इस कार्यकारी अमले की तादाद बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है. इससे योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेहिता बढ़ेगी, साथ ही सभी गतिविधियों को पूरी पारदर्शिता से अंजाम दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार तय मानकों के आधार पर देश के हर राज्य को एक निश्चित राशि भी देगी. अधिनियम में ग्रामीण आजीविका निर्माण के स्थाई स्रोत विकसित करने पर जोर दिया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और विलम्बित मजदूरी देने का प्रावधान भी रखा गया है. इसमें तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो राज्य सरकार तय की गई दरों एवं शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता परिवार को बेरोजागारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी.

87 किलो डोडाचूरा जब्त

इंदौर, 7 जनवरी. नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत तेजाजीनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब से इंदौर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 87 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई जा रही है. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया गया है. तेजाजीनगर थाना प्रभारी देवेन्द्र मरकाम ने बताया कि यह कार्रवाई एबी रोड बायपास स्थित आउटर कॉलोनी क्षेत्र में नियमित चेकिंग के दौरान की गई. यादव ढाबे के पास सर्विस रोड पर खड़े एक ट्रक को संदिग्ध मानते हुए जब रोका गया तो चालक घबरा गया और वाहन स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगा.

हलफनामा के साथ पेश हो छात्रों की जानकारी

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिका की सुनवाई

जबलपुर, 7 जनवरी. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सीबीआई की जांच में अनसूटेबल पाये गये छात्र का स्थानांतरण सुटेबल कॉलेज के किये जाने के संबंध में हलफनामा के साथ जानकारी पेश करने के निर्देश जारी किये।

युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से प्रदेश में फर्जी तरह से संचालित नर्सिंग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच के निर्देश दिये थे। सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाये गये छात्रों का स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों का स्थानांतरण सीबीआई जांच में सूटेबल कॉलेज में किये जाने के आदेश जारी किये थे।

अवमानना याचिका पर आए आदेश

आदेश के बावजूद भी छात्रों को स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में न किये जाने पर याचिकाकर्ता की तरफ से अवमानना आवेदन दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई के दौरान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियमों में किसी जिले के छात्रों को उसी जिले में स्थानांतरित करने संबंधी प्रावधान के कारण हजारों छात्रों को स्थानांतरित करने में सीटों की समस्या आ रही है।

मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट 11 से होगी

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 'विकसित एम.पी. ञ2047' विज़न को साकार करने और प्रदेश के स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को अगले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से 11 एवं 12 जनवरी 2026 को रवींद्र भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. सोमवार 12 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट में सहभागिता करेंगे. समिट में मध्यप्रदेश सहित देशभर से स्टार्ट-अप्स, निवेशक, इनक्यूबेटर्स, उद्योग प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य हितधारक शामिल होंगे. यह आयोजन स्टार्ट-अप्स को निवेश, नेटवर्किंग, नीति संवाद एवं नवाचार प्रदर्शन के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा.

मौसम | उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं से कांपा प्रदेश

प्रदेश में बढ़ी सर्दी, कई जिलों में शीतलहर

भोपाल, 7 जनवरी.उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं के प्रभाव से मध्य प्रदेश में सर्दी लगातार तीव्र होती जा रही है. रात में प्रदेश के कई शहरों में तापमान एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

अमरकंटक और हिल स्टेशन पचमढ़ी में मैदानों में ओस की बूंदें जम गईं, जबकि राजगढ़ में न्यूनतम तापमान गिरकर मात्र 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भोपाल और राजगढ़ में तीव्र शीतलहर का असर देखने को मिला, वहीं शाजापुर, शहडोल, सिवनी, मंदसौर और सीहोर जिलों में शीतलहर का प्रभाव बना रहा.

पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान नर्मदापुरम और रीवा संभागों के जिलों में 2.2 से 3.0 डिसे तक बढ़ा, जबकि अन्य संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. चंबल संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिसे तक कम रहा. वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभागों में तापमान सामान्य से 1.9 से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान भोपाल संभाग में 2.4 डिसे तक बढ़ा, जबकि भोपाल, जबलपुर और शहडोल संभागों में यह सामान्य से 1.9 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा.

दतिया में अति घना कोहरा छाया रहा, जबकि भोपाल, ग्वालियर, राजगढ़ और खजुराहो में घना कोहरा दर्ज किया गया. कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा. उमरिया और कल्याणपुर (शहडोल) जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा, जबकि नरसिंहपुर जिले में शीतल दिन दर्ज किया गया. दिन का सबसे कम अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस श्योपुर में और सबसे अधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया.

दुर्घटना टालने वाले 15 रेलकर्मी सम्मानित

भोपाल,7 जनवरी . भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी द्वारा ड्यूटी के दौरान सतर्कता, सूझ-बूझ एवं त्वरित कार्यवाही से संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालने वाले 15 रेलकर्मियों को दिनांक 7 जनवरी 2026 को सम्मानित किया गया. सम्मानित रेलकर्मियों में इटारसी के गुड्स ट्रेन मैनेजर राज कुमार पुरबिया, राहुल साहू, हरि प्रसाद अहिरवार, कमलेश कुमार अहिरवार, इटारसी के ट्रैकमेन कन्हैया लाल, विशाल थातिया, बीना के ट्रैकमेन शिवराज सिंह, हेमराज अहिरवार, नर्मदापुरम के ट्रैकमेन गौरव कुमार, विदिशा के ट्रैकमेन अमित राजपूत, छनेरा के ट्रैकमेन सोहन लाल, अशोकनगर के प्वांट्समेन मनोज कुमार , बरखेड़ा के उप स्टेशन प्रबंधक शहजाद खान, चचोड़ा-बीना गंज के उप स्टेशन प्रबंधक राहुल कुमार मीना एवं व्यावरा राजगढ़ के प्वांट्समेन हरिओम जाटव शामिल हैं.

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, इंदौर संभाग क्रमांक-02
जी-13, प्रथम 'तल' एम.आई.जी. कॉलोनी, एम.आई.जी. थाने के पीछे, इंदौर (म.प्र.) मो. नं. : 9425601512
E-mail Id : mpphidclindore2@gmail.com
निविदा आमंत्रण सूचना - 39/2025-26
म.प्र.पु.आ.एवं अधो.वि.नि., इंदौर संभाग क्र. 02, इंदौर द्वारा 100 सीटर महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास भवन निर्माण, हरसूद (जिला खण्डवा) हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र **दिनांक 28.01.2026 तक** खरीदे जा सकते हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/123859/2026 **परियोजना यंत्री**

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60